दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 08 मई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 217

महत्वपूर्ण एवं खास

यूएन ने भारत को भेजे 10 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एक करोड़ मास्क

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में लगातार कोविड-19 के मरीज बढ़ने के कारण देशभर के अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन व अन्य जरूरी मेडिकल सामग्रियों के अभाव से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे मे दुनिया के अन्य देश लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने भी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को करीब 10 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। इसके साथ ही करीब एक करोड़ मेडिकल मास्क भी भेजे हैं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में मदद करने के लिए कई देश आगे आए हैं और कई देश और विदेशी एजेंसियां भारत को जरूरी मेडिकल सप्लाई भेज रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बृहस्पतिवार को अपने बयान में कहा, 'भारत में संयुक्त राष्ट्र का दल महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों सरकारों का सहयोग कर रहा है।उन्होंने कहा कि यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए) ने करीब 10 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एक करोड़ मेडिकल मास्क और 15 लाख से अधिक फेस शील्ड भारत को भेजे हैं। संयुक्त राष्ट्र के दल ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भी खरीदे हैं।

डब्ल्यूएनसी से 41 नौसैनिक की एक टुकड़ी धनवंतरी में तैनात

अहमदाबाद (आरएनएस)। कोविड महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई का डटकर मुकाबले करने और कुशल मैनपावर क्षमता बढ़ाने के लिए पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी) से 41 नौसैनिक की एक टुकड़ी, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी, पैरामेडिक्स और सहयोगी स्टाफ शामिल हैं को प्रधानमंत्री कोविड केयर अस्पताल (धनवंतरी), अहमदाबाद में 06 मई को तैनात किया गया। यह 29 अप्रैल, 2021 को अस्पताल में तैनात 57 नौसेना चिकत्सा टीम से अलग है। टीम को दो महीने के लिए तैनात किया जा रहा है। यह टीम कोविड रोगियों को इलाज और देखभाल में अस्पताल प्रशासन की मदद करेगी।

रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 2960 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेल उभरती चुनौतियों का सामना करते हुए और नए उपायों की तलाश के साथ में देश के विभिन्न राज्यों की मांग पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान को निरंतर जारी रख लोगों को राहत पहुंचा रही है।रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 185 टैंकरों में लगभग 2960 मीट्रिक टन चिकित्सा उपयोग हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। अब इस अभियान के अंतर्गत 47ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। भारतीय रेल राज्यों की मांग पर यथासंभव मात्रा में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर लगातार काम कर रही है। अब तक महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 729 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 249 मीट्रिक टन, हरियाणा को 305 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन और दिल्ली को 1334 मीट्रिक टन ऑक्सीज़न की आपूर्ति की गई।

भारत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में फिर सामने आए 4 लाख से अधिक नए मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का भय तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो गांव तक में अपने कदम रख चुका है। पिछले दो दिन से लगातार देश में चार लाख से दैनिक मामले आ रहे हैं। मसलन पिछले 24 घंटे मे एक बार फिर से नए संक्रमण के मामले 4.14 लाख से ज्यादा दर्ज किये गये। इस दौरान 3915 लोगों की मौत हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले एक दिन में कुल 4,14,188 नए मामले सामने आए और 3915 लोगों की मौत हुई। इस प्रकार देश में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामले 2,14,91,598 हो गए हैं, जिनमें 1,76,12,351 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 2,34,083 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। जबकि

अस्पताल में इलाज कराने वाले सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 36,45,164 पहुंच गई है।

महाराष्ट्र में कोरोना के 62,194 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा कर्नाटक प्रभावित दिख रहा है। कर्नाटक में 49,058 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह केरल (42,464), तमिलनाडु (24,898), पश्चिम बंगाल (18,431), ओडिशा (10,521), पंजाब (8,874), उत्तराखंड (8,517), असम (4,936), जम्मू-कश्मीर (4,926), हिमाचल प्रदेश (3,942), गोवा (3,869) और मेघालय ने पिछले 24 घंटों में 347 नए मामले सामने आए हैं।

महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौतें – मंत्रालय के अनुसार 13 राज्यों में पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अब तक की सबसे अधिक मौतें हुई। महाराष्ट्र में भी मौतों की संख्या में कमी आती नहीं दिख रही है। बीते 24 घंटे में यहां 853 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली में मौत का आंकड़ा 300 से अधिक रहा। छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक की जान गई। तमिलनाडु में 195, राजस्थान में 161, प. बंगाल में 117, केरल में 63 और जम्मू-कश्मीर में 52 लोगों की मौत हुई। गुरुवार 6 मई को लगातार 16वां दिन रहा जब संक्रमण के मामले तीन लाख से अधिक रहे। महाराष्ट्र में 50 हजार से अधिक मामले आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा जहां गुरुवार को 49,058 मामले सामने आए।

पिछले 10 दिनों में हर घंटे हुई डेढ सौ मौतें – स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिन से कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा रोज तीन हजार से ज्यादा आ रहा है। 10 दिन में कोरोना के कारण 36 हजार 110 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में हर घंटे कोरोना से डेढ़ सौ से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है। भारत में जितनी तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वह एक दिन में किसी भी देश में आए मामलों में सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अमेरिका में पिछले 10 दिनों में कोरोना से 34 हजार 798 मौतें हुई हैं, जबकि ब्राजील में पिछले 10 दिन में ये आंकड़ा 32 हजार 692 रहा। इसी अवधि में मैक्सिको में सबसे अधिक 13 हजार 897 मौतें हुई जबकि ब्रिटेन में 13 हजार 266 मौतें हुई। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटे राज्य उत्तराखंड में 151 लोगों की जान गई जो कि देश में 10वां सबसे अधिक आंकड़ा रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में ही कुंभ मेले का आयोजन हुआ था।

देश के दो दर्जन राज्यों में 15 फीसदी कोरोना संक्रमण दर– केंद्र सरकार ने कहा कि 12 राज्यों में कोविड-19 के एक लाख से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। जबकि सात राज्यों में 50 हजार से एक लाख मरीज अब भी संक्रमण की चपेट में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने शुक्रवार को कहा कि देश के 24 राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर 15 प्रतिशत से अधिक है जबकि नौ राज्यों में यह दर पांच से 15 प्रतिशत के बीच है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ वे राज्यहैं जहां कोविड-19 के दैनिक मामलों में निरंतर गिरावट या स्थिरता दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने कहा कि देश में 16.96 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं और लगभग 82ल्न मामले रिकवर हो चुके हैं। मृत्यु दर 1.09 प्रतिशत है। कल 4,14,188 नए मामले दर्ज़ किए गए।

देश में अब तक 16 करोड 49 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए

नईदिल्ली (आरएनएस)। वैश्विक महामारी की दूसरी लहर और कोविड-19 के मामलों में अप्रत्याशित तेके मद्देनजर भारत की चुनौतियों और जरूरतों के लिये विश्व समुदाय मदद कर रहा है। भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि विश्व सहायता को तुरंत और कारगर तरीके से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाये। यह निरंतर चलने वाली गतिविधि है। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न उपायों और जरियों से सहायता दी जाये, ताकि इस संकट की घड़ी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी से लड़ने में मजबूती मिले।

30 राज्यों में 18-44 आयुवर्ग के 11,80,798 लोगों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है। इन राज्यों में अंडमान-नीकोबार द्वीप समूह (330), आंध्रप्रदेश (16), असम (220), बिहार (284), चंडीगढ़ (2),छत्तीसगढ़ (1,026), दिल्ली (1,83,679), गोवा (741), गुजरात (2,24,109), हरियाणा (1,69,409), हिमाचल प्रदेश (14), जम्मू-कश्मीर (21,249), झारखंड (77), कर्नाटक (7,068), केरल (22), लद्दाख (86), मध्यप्रदेश (9,823), महाराष्ट्र (2,15,274), मेघालय (2), नगालैंड (2), ओडिशा (28,327), पुदुच्चेरी (1), पंजाब (2,187), राजस्थान (2,18,795), तमिलनाडु (8,419), तेलंगाना (440), त्रिपुरा (2), उत्तरप्रदेश (86,420), उत्तराखंड (17) और पश्चिम बंगाल (2,757) शामिल हैं।

खानाबदोश, साधुओं व कैदियों को बिना पहचान पत्र के लगेगी कोरोना वैक्सीन, केंद्र सरकार ने जारी किये आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना के कोहराम को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक एसओपी जारी करके निर्देश दिये हैं कि देश में खानाबदोश, भिखारियों, साधुओं और कैदियों को बिना किसी पहचान पत्र के कोरोना टीका लगाया जाएगा।

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान में और तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान में ऐसे लोगों के ऐसे

समूहों में विभिन्न धर्मों के साधु संतों समेत सभी खानाबदोश, भिखारियों, जेल के कैदी, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में बंद कैदी, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले लोगों का भी टीकाकरण किया जाएगा, जिनके पास कोई फोटो पहचान पत्र नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिला कार्यबल के लिए एक एसओपी जारी करते हुए कहा है कि अब वैध पहचान पत्र वाले एक प्रमुख सूत्रधार की पहचान की जाएगी, जो इन समूहों के वैक्सीनेशन के लिए सेंटर प्वाइंट होगा। केंद्र ने यह भी कहा है कि जेल अधिकारियों और वृद्धाश्रम के अधिकारी प्रमुख सूत्रधार के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें जिला कार्यबल को ऐसे लोगों को कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनके पास फोटो पहचान पत्र नहीं है। दरअसल, कोरोना के खिलाफ किए जा रहे हर एक वैक्सीनेशन का डाटा एक सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत किया जाना है। इसके लिए वैक्सीन लगवाने वाले के पास एक वैध पहचान पत्र होना जरूरी माना गया है। ऐसे में जिन लोगों के पास कोई भी फोटो पहचान पत्र नहीं होगा, उन्हें वैक्सीन लेने में समस्या हो सकती है और ऐसे समूह से संक्रमण के मामलों के बढ़ने का खतरा भी बना रहेगा।

कोरोना के स्वरूपों का वैज्ञानिक तरीके से पता लगाए सरकार

» प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी की पाती

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के सभी स्वरूपों का वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाने के साथ ही पूरी दुनिया को इस बारे में अवगत कराया जाए तथा सभी भारतीय नागरिकों को जल्द टीका लगाया जाए।

प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राहुल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर के लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हो गया है और ऐसे में गरीबों को तत्काल आर्थिक मदद दी जाए ताकि उन्हें पिछले साल की तरह पीड़ा से नहीं गुजरना पड़े।

पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की इस सुनामी के अप्रत्याशित संकट में भारत के लोग आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होने चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप देश के लोगों को इस पीड़ा से बचाने के लिए जो भी संभव हो, वह करिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर छह लोगों में से एक व्यक्ति भारतीय है। इस महामारी से अब यही पता चला है कि हमारा आकार, आनुवांशिक विविधता और जटिलता से भारत में इस वायरस के लिए बहुत ही अनुकूल माहौल मिलता है कि वह अपने स्वरूप बदले तथा अधिक खतरनाक स्वरूप में सामने आए। मुझे डर इस बात का है कि जिस डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट को हम देख रहे हैं, वह शुरुआत भर हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि इस वायरस एवं इसके विभिन्न स्वरूपों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाए। सभी नए म्यूटेशन के खिलाफ टीकों के असर का आकलन किया जाए। सभी लोगों को तेजी से टीका लगाया जाए। पारदर्शी रहा जाए और शेष दुनिया को हमारे निष्कर्षों के बारे में अवगत कराया जाए।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास कोविड के खिलाफ टीकाकरण को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं हैं और सरकार ने उसी समय इस महामारी पर विजय की घोषणा कर दी जब यह वायरस फैल रहा था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विफलता के कारण आज राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन अपरिहार्य लगता है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इस स्थिति को देखते हुए कमजोर तबकों के लोगों को वित्तीय मदद और खाद्य सामाग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि लॉकडाउन के कारण गरीबों को उस पीड़ा को न झेलना पड़े जो उन्हें पिछले साल के लॉकडाउन के समय झेलनी पड़ी थी। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस संकटकाल में विभिन्न पक्षों को विश्वास में लिया जाए ताकि सब मिलकर भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम कर सकें।

ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश को बताया सही

» केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

नई दिल्ली (आरएनएस)। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने वाली केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कर्नाटक हाईकोर्ट के 1200 मिट्रिक टन ऑक्सीजन देने के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को राज्य के लिए 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश अच्छी तरह से जांचने के बाद और शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग के तहत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने कैलिब्रेटेड अभ्यास किया है और हमें इसमें दखल देने का कोई कारण भी नहीं दिखता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना के 3.95 लाख मामलों पर कर्नाटक के मुताबिक 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक की न्यूनतम आवश्यकता है। बता दें कि बीते दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य में तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन (एलएमओ) की रोजाना आपूर्ति 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने के निर्देश दिए थे।

भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व चिकित्सकों ने आम मरीजों के लिए ऑनलाइन परामर्श देना शुरू किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, आईएएस और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक (डीजीएएफएमएस) सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, पीएचएस, ने देश के आह्वान का जवाब देने के लिए आगे आने वाले सेना के पूर्व डॉक्टरों को संबोधित किया है। सेना के पूर्व डॉक्टर अब भारत के सभी नागरिकों के लिए ई-संजीवनी ओपीडी पर सेना के पूर्व डॉक्टरों द्वारा ऑनलाइन परामर्श सेवा के लिए उपलब्ध होंगे।

ई-संजीवनी ओपीडी भारत सरकार का प्रमुख टेलीमेडिसिन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक), मोहाली, भारत सरकार के तत्वावधान में विकसित किया गया है और यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म किसी भी भारतीय नागरिक को मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। हालांकि, कोविड मामलों में वृद्धि के साथ, डॉक्टरों की मांग बढ़ रही है, लेकिन, डॉक्टरों के कोविड वॉर्ड की ड्यूटी से हट जाने के कारण डॉक्टरों की कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में सेना के पूर्व डॉक्टर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की चिकित्सा शाखा सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करता है। चिकित्सा शाखा ने देश के सामान्य नागरिक रोगियों के लिए इस पूर्व-रक्षा ओपीडी को शुरू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ समन्वय किया है। आईडीएस मेडिकल के उपाध्यक्ष ने सेवानिवृत्त एएफएमएस डॉक्टरों की सभी सेवानिवृत्त बिरादरी से इस मंच से जुड़ने और संकट के इस समय में भारत के नागरिकों को बहुमूल्य परामर्श प्रदान करने का आग्रह किया है, जब देश कठिन समय से गुजर रहा है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा... परमाणु ऊर्जा विभाग महामारी से लड़ने में देश के कोविड बुनियादी ढांचे में सहायता कर रहा है

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भाभा परमाणु केंद्र और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) कोविड संबंधित उपकरणों तथा टेक्नोलॉउपलब्ध कराने के जरिये महामारी से लड़ने में देश की सहायता कर रहे हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक

में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के दौरान जन कल्याण के लिए की गई पहलों की सराहना की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोबाल्ट सोर्स का उपयोग करने के जरिये पीपीई किट्स के स्टरलाइजेशन के लिए किए गए प्रोटोकॉल के विकास में पीपीई किट्स के पुर्नउपयोग की संभावना है। इसी प्रकार, एचईपीए फिल्टर टेक्नोलॉके उपयोग के जरिये एन-99 मास्क का विकास किया गया है। उन्होंने ने कहा कि यह मास्क एन-95 मास्क से बेहतर है और एन-99 मास्क पहले ही तीन स्वतंत्र प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉको व्यापक स्तर पर उत्पादन के लिए ट्रांसफर किया गया है क्योंकि यह टिकाऊ तथा एन-95 मास्क की तुलना में सस्ता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने पावर्ड रेस्पिरेटर्स, रीफर, पोर्टेबल प्लाज्मा स्टरलाइजेशन तथा मेडिकल अपशिष्टों के लिए प्लाज्मा इनसिनेरेशन टेक्नोलॉके अतिरिक्त, आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के लिए सफलतापूर्वक रिएजेंट्स को भी डेवेलप किया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि टाटा मेमोरियल के सभी अस्पतालों में कोविड से संक्रमित रोगियों के लिए 25 प्रतिशत बेड जो लगभग 600 हैं, आरक्षित कर दिये गये है। 6 एलपीएम के लगभग 5,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स विदेशों से दान के रूप में टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी) द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं और इनमें से अधिकांश देश के अन्य कैंसर अस्पतालों में दे दिए जाएंगे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि कोविड-19 की गंभीरता के लिए आनुवंशिक संवेदनशीलता निर्धारित करने के लिए वर्तमान में टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से 'कोविड-19 के लिए निगरानी जांच' अध्ययन किया जा रहा है।